an>

Title: Need to increase the cost fixed by the central government for survey/resurvey under National Land Records Modernisation Programme in the country.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र के किसान पिछले कई वर्षों से एक मुसीबत में हैं। किसानों को राष्ट्रीय भूमि अभिलेख कार्यालय के माध्यम से अपनी जमीन का सर्वे कराने और सर्वे के हिसाब से आपस में बंटवारा करने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन, पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र शासन ने सर्वे की कार्य प्रणाली पर रोक लगा दी है। सर्वे करते वक्त पारंपरिक पद्धति के बजाय सैटेलाइट सर्वे, इ.टी.एस. सिस्टम से सर्वे करना, डी.जी.पी.एस. सिस्टम से सर्वे करना, ऐसे कई अच्छे सुझाव महाराष्ट्र शासन ने रखा हैं। लेकिन, इसमें एक मुसीबत यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र के पास जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें महाराष्ट्र सरकार ने उसके बहुत ज्यादा चार्ज प्रस्तावित किए हैं। आज के समय में एक सर्वे करने का चार्जेज 15,000 रुपये प्रति किलोमीटर है। उसकी बजाय अब महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 रुपये प्रति किलोमीटर का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास रखा है।

महोदया, मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो नया प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है, उसे तुरंत मंजूरी दें, लेकिन उसे मंजूरी देते वक्त उसे 50,000 रुपये प्रति किलोमीटर की जगह पर 25,000 रुपये प्रति किलोमीटर के चार्ज को मंजूरी देकर किसानों को राहत देने की कोशिश करें।